जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 22 जून 2021

क्योंकि चौकीदार ही चोर है!!!

संवाद के अधिकारियों ने ही लगाया लाखों रुपयों का चूना!!!

नेगोशिएशन में रेट कम करने की जगह बढ़ा दी रेट!!!

राजस्थान संवाद में भ्रष्टाचार चरम पर!!!

भाग-5

SPECIAL REPORT

एक कागज ने खोली भ्रष्टाचार की पोल!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2018 मे राजस्थान संवाद द्वारा प्रिंट मीडिया मे दिये जाने वाले विज्ञापनों की डिजाइन,प्रॉडक्शन और प्रसारण की सेवाओं के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा संख्या 915 दिनांक 24/08/2018 आमंत्रित की गयी|बिडिंग डोक्यूमेंट के अनुसार यह टेंडर 5 करोड़ का था(जानकारों के अनुसार इस टेंडर को बाद मे 20-25 करोड़ तक पहुचा दिया गया)|निविदा दाखिल करने की अंतिम तिथि 03/09/2018 थी|इस निविदा की टेक्निकल बिड़ 04/09/2018 एवं वित्तीय बिड़ 24/09/2018 को खोली गयी|यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था जैसा अन्य निविदाओं मे होता आया है|लेकिन यहाँ से कहानी मे मोड आता है,इस संबंध मे हमे प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार;

1. **इस निविदा के वित्तीय प्रस्ताव एजेंसियों के प्रतिनिधियों एवं कमिटी के सदस्यों के समक्ष दिनांक 24/09/2018 को खोली गयी|इस निविदा के संबंध मे 20 एजेंसियां तकनीकी रूप से सक्षम पायी गयी|**
2. **मै. चंद्रा ट्रायो सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा दिनांक 03/09/2018 को पत्र प्रेषित कर आवेदन किया कि उनके द्वारा वित्तीय प्रस्ताव के संदर्भ मे त्रुटिवश दर 6%के स्थान पर 5% हो गयी है,जिसे ई पोर्टल पर पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है|अतः उनकी दर को 5% के स्थान पर 6% मानी जाये|**
3. **इसी प्रकार मैं. एस.जी. एडवर्डटाईजिंग द्वारा दिनांक 18/09/2018 एवं मैं. आनवर्ड एडवर्डटाईजिंग के द्वारा दिनांक 20/09/2018 को पत्र प्रेषित कर दर(4.9% एवं 5% क्रमशः)भुलवश अंकित करने की बात कही गयी|**
4. **इस प्रकार दिनांक 24/09/2018 को खोले गए वित्तीय प्रस्ताव मे 6% दर न्यूनतम पायी गयी|**
5. **राजस्थान संवाद की प्रिंट मीडिया(सजावटी)विज्ञापन संबंधी कार्य की दर के निर्धारण हेतु दिनांक 20/09/2018 को गठित समिति द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रस्तावो के आधार पर न्यूनतम औसत दर 7.99 का आंकलन किया गया|**

आरटीपीपी एक्ट 2012 मे गलती की सजा टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना है,ना कि उसकी गलती को सुधारने का मौका देकर उपकृत करना|

टेंडर प्रक्रियाओं मे अधिकतम पारदर्शिता के लिए ही राजस्थान सरकार द्वारा आरटीपीपी एक्ट 2012 अस्तित्व मे लाया गया था,लेकिन भ्रष्टाचारियो के कृत्यों को देखकर लगता नहीं है कि इस एक्ट का कोई औचित्य रह गया है|इस निविदा मे न केवल जिम्मेदारों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर फर्म विशेष को फायदा पहुंचाया गया बल्कि जम कर राजस्व को भी नुकसान पहुंचाया गया| आरटीपीपी एक्ट 2012 मे कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि तकनीकी और वित्तीय बीड्स मे एक बार नामांकन करने के बाद उनमे किसी प्रकार काँट-छाँट करना,हेराफेरी की जा सके|और क्या यह संभव है कि यह गलती एक फर्म से ना होकर तीन-तीन फ़र्मों से हो?इतना ही नहीं जिन जिम्मेदारों पर राजस्व हित मे इन एजेंसियों से नेगोशिएशन कर रेट और कम करवाने का दारोमदार था,वही जिम्मेदार इन एजेंसियों से नेगोशिएशन नहीं कर,न्यूननम दर(जिसे फ़र्मों की गलतियों के बाद 6% स्वीकार किया जाना था) को भी 7.99% तक ले गए|सवाल यह है कि क्या राजस्थान संवाद के अधिकारी इतने भोले है कि उन्हे किसी की नियत का पता ही नहीं लगता या फिर इतने शातिर की अपने फायदे के लिए सरकारी खजाने को भी चुना लगाने से नहीं चूकते|बहरहाल यह सरकार और जांच एजेंसियों को तय करना है कि इस मामले मे आगे क्या किया जाए|

268.

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

आज दिनांक 24.09.2018 को NIB No. 915 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा प्रिन्ट मीडिया (सजावटी) विज्ञापन एमैनलमेंट के लिये तकनीकी दस्तावेजो / डिजाईन / प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन के पैनल में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया मे तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई एजेन्सियो से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात वित्तीय प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये।

269. वित्तीय प्रस्ताव एजेन्सियो के प्रतिनिधियों एवं कमेटी के सदस्यो के समक्ष खोले गये। जिसका विवरण संलग्न है :-

1. तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई समस्त 20 एजेन्सियो के वित्तीय प्रस्ताव राजस्थान संवाद को प्राप्त हुए है।
2. मैसर्स चन्द्रा ट्रायो सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा दिनांक 03.09.2018 को पत्र प्रेषित कर आवेदन किया गया है कि उनके द्वारा त्रुटिवश दर 6% के स्थान पर 5% हो गई है, जिसे ई-पोर्टल पर पुनः ठीक नही किया जा सकता है। अतः उनकी दर को 5% के स्थान पर 6% माना जायें।
3. इसी प्रकार मैसर्स एस.जी. एडवरटाइजिंग द्वारा दिनांक 18.09.2018 एवं मैसर्स ऑनवर्ड एडवरटाइजिग के द्वारा दिनांक 20.09.2018 को पत्र प्रेषित कर दर (4.90% एवं 5% क्रमशः) राजस्थान संवाद की मानते हुए भूलवश अंकित करने की बात कही गई है।
4. इस प्रकार दिनांक 24.09.2018 को खोले गये वित्तीय प्रस्ताव में 6% दर न्यूनतम पाई गई है।
5. राजस्थान संवाद की प्रिन्ट मीडिया (सजावटी) विज्ञापन संबंधी कार्य की दर के निधारण हेतु दिनांक 20.09.2018 को गठित समिति द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों के आधार पर न्यूनतम औसत (Average) दर 7.99% का आंकलन किया गया है।

एजेन्सियों से प्राप्त दरो के आधार पर नेगोशियेसन हेतु दिनांक 25.09.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे समस्त एजेंसी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

संवाद की वित्तीय सलाहकार श्रीमति अनुपमा शर्मा के हस्ताक्षर

(ED/FA)

संवाद के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री शिव चंद मीणा के हस्ताक्षर

Sr. Mgr

डीआईपीआर के उप निदेशक(विज्ञापन)श्री रामकिशन तंवर के हस्ताक्षर

(AD Advt)

पोर्टल के चीफ एडिटर की अनुमति पश्चात कोई भी समाचार पत्र-पत्रिका,न्यूज एजेंसी इस रिपोर्ट या इसके अंश को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है।

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर आरटीपीपी एक्ट/रूल्स के 2012 की किन नियमों/प्रावधानों के तहत तकनीकी बिड़ मे सफल रही एजेंसियों के द्वारा वित्तीय बिड़ मे किए गए संशोधनों को स्वीकार किया गया?
2. इस मामले मे मै. एस.जी. एडवर्डटाईजिंग द्वारा न्यूनतम दर 4.90% दी गयी थी इस फर्म द्वारा अपनी भूल सुधार कर कितनी रेट पर काम करना स्वीकार किया गया?मैं. आनवर्ड एडवर्डटाईजिंग के द्वारा न्यूनतम दर 5 % दी गयी थी इस फर्म द्वारा अपनी भूल सुधार कर कितनी रेट पर काम करना स्वीकार किया गया?
3. आखिर किस आधार पर समिति के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा राजस्थान संवाद की प्रिंट मीडिया(सजावटी) विज्ञापन संबंधी कार्य की न्यूनतम औसत दर 7.99% का आंकलन किया गया?जबकि एस.जी. एडवर्डटाईजिंग द्वारा न्यूनतम दर 4.90% दी गयी थी|और तीनों फ़र्मों की भूल सुधार के बाद न्यूनतम दर 6% पायी गयी थी?
4. इस निविदा मे किन किन एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया?
5. मै. चंद्रा ट्रायो सर्विसेज प्रा.लि.,मै. एस.जी. एडवर्डटाईजिंग मैं. आनवर्ड एडवर्डटाईजिंग के अलावा और कितनी एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया?उन अन्य एजेंसियों द्वारा ई पोर्टल पर वास्तविक दर कितनी भरी थी?उनके द्वारा अपनी भूल सुधार कर कितनी न्यूनतम दर पर काम करना स्वीकारा गया?
6. नेगोशिएशन के बाद इस निविदा की अंतिम स्वीकृत दर क्या निर्धारित की गयी?
7. यदि ई पोर्टल पर दर्ज रेटों के आधार पर ही यह टेंडर किया जाता तो 5 करोड़ का 4.9% के हिसाब से 24.5 लाख का भुगतान एजेंसियों को किया जाता, 5 करोड़ का 6% के हिसाब से 30 लाख का भुगतान एजेंसियों को किया जाता और 5 करोड़ का 7.99% के हिसाब से 39.95 लाख का भुगतान एजेंसियों को किया जाता,इस प्रकार इस दर को 4.9% से 6% करने पर 5.5 लाख के राजस्व की हानि अथवा इस दर को 4.9 से 7.99 करने पर 15.45 लाख के राजस्व की हानि पहुचाई गयी है|लाखो रुपयों के इस अतिरिक्त भुगतान का दोषी कौन?
8. कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड?आखिर कौन कौन है भ्रष्टाचार के इस खेल मे शामिल?
9. कौनसी एजेंसी करेगी इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच?वित्त विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या और कोई संस्था?
10. क्या वाकई यह निविदा (NIB 915) मात्र 5 करोड़ की थी या फिर इसे 20-25 करोड़ पहुंचाया गया?क्या यह खेल मात्र लाखो का है या फिर करोड़ों का?
11. जब राजस्थान संवाद नामक संस्था अपने आप को लोक प्राधिकरण नहीं मानती और सूचना के अधिकार के तहत आम जन को सूचना नहीं देती है तो फिर यह संस्था लोक प्राधिकरण होने के नाते RTPP ACT 2012 के प्रावधानों की पालना क्यूँ कर रही है?
12. क्या इस मामले मे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और संबन्धित फ़र्मों से वसूली की जाएगी?
13. आखिर इस खेल को अंजाम देने की कितनी न्योछावर ली गयी है जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा?